TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 224
दि. 15.12.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

सीएम योगी बोले- यूपी के नए कैप्टन हैं पंकज चौधरी, दो-तिहाई बहुमत से 2027 में बनेगी सरकार

लखनऊ (जीएनएस)।

भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते आठ वर्षों में प्रदेश के विकास पर चर्चा की और कहा कि संगठन और सरकार मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यूपी के नए कैप्टन हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई सीटों पर जीत हासिल करेगी। पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप नई गति के साथ सरकार व संगठन मिलकर विकसित यूपी के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। सीएम राम मनोहर लोहिया विधि विवि में नए प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

सीएम ने निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में साढ़े तीन वर्ष से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हर कार्यक्रम को गति देने में योगदान दिया। कार्यकताओं से कहा कि चुनावी लड़ाई बूथ पर होती है इसलिए वह सबसे मजबूत होना चाहिए। एक जिले के दौरे का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि विरोधियों द्वारा भरी गई मतदाता सूची में कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम थे। एक जिले में ऐसा फॉर्म भरा गया जहां मतदाता की आयु 20 वर्ष, पिता की 30 और बाबा की आयु 40 साल है।

फर्जी वोट पर करें आपत्तिः एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकताओं से कहा कि हर बूथ से फर्जी नाम पर आपत्ति दर्ज कराएं। नाम जोड़ने व काटने के लिए समय है। अभी तीन चौथाई मेहनत करेंगे तो चुनाव में सिर्फ एक चौथाई मेहनत ही करनी पड़ेगी।

एसआईआर के जो प्रपत्र जमा नहीं हो पाए, युद्ध स्तर पर उन्हें जमा कराइए।

परिवर्तन करने में हुए सफल, बिना भेदभाव युवाओं को दी नौकरी

योगी ने कहा कि साढ़े 8 वर्ष में यूपी में हम जो परिवर्तन करने में सफल हुए हैं वह पीएम मोदी के मार्गदर्शन और हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। यूपी को बीमारू राज्य से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया। आज यूपी दंगा, माफिया व अपराधमुक्त होकर पर्यटन, निवेश के लिए देश के बेहतरीन राज्यों में शामिल है। हमने बिना भेदभाव पौने नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। डेढ़ करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में नौकरी व रोजगार से जोड़ा। निवेश,

सुरक्षा, कानून के राज से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजनाएं धरातल पर उतरीं।

25 को आएंगे पीएमः सीएम ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी कार्यक्रम है। राजधानी में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी की 65-65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। संग्रहालय भी है। इसका उद्घाटन व रैली लखनऊ में होगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं से कहा कि एसआईआर पूरा कराएं, फिर अयोध्या में रामलला और यहां राष्ट्र प्रेरणा

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस... पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में इजरायली लोगों पर हुए हमले की निंदा की

सिडनी में हनुक्का पर्व पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों की जान गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। यह घटना बोंडी बीच पर हुई।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का का त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर हुए आतंकी हमले पर भारत के

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीड़ित परिवारों के लिए दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता दोहराई। इस आतंकी हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है।

पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए भारत की जनता की ओर से उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुटता से खड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर आज हुए भयावह आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं।

'बिहार में एमएलए और मंत्री के रूप में...', नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर सीएम, मोदी ने दी बधाई

(जीएनएस)।

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है. वे एक युवा और कर्मठ नेता हैं, जिन्हें संगठन का काफी अनुभव है. बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है.

उन्होंने नितिन नबीन को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कहा, ह्वनितिन नवीन जी ने भाजपा के एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है. वह एक युवा, कर्मठ और संगठनात्मक अनुभव के धनी नेता हैं, जिनका

बिहार में एक विधायक और मंत्री के रूप में कई कार्यकालों का एक प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया है.'

उनकी ऊर्जा पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेगी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, ह्ववह अपने विनम्र स्वभाव और जमीन से जुड़ी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक मजबूत करेगी. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नबीन को दी बधाई

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने कहा, ह्वमाननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं की ओर श्री नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं.'

उपराष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति-एन्क्लेव में सिविल सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की

उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक सेवा में धैर्य, धर्म और जवाबदेही पर जोर दिया

उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में यूपीएससी और प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका को रेखांकित किया

धैर्य और दूसरों को ध्यान से सुनना मानवीय शासन के मूल तत्व हैं: उपराष्ट्रपति

सरदार पटेल का रियासतों का एकीकरण एक बेमिसाल वैश्विक उपलब्धि है: उपराष्ट्रपति

उच्च स्वर में कही गयी बातें प्रचलित हो सकती हैं, लेकिन सार्थक बहस स्थायी सार्वजनिक विश्वास का निर्माण करती है: उपराष्ट्रपति

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति एनक्लेव, नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। ये अधिकारी हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) में विशेष फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं।

भारत के "लौहपुरुष" सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए,

उपराष्ट्रपति ने रियासतों के एकीकरण और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि जहाँ ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, जहाँ लोग एक ही भाषा बोलते थे, वहीं सरदार पटेल ने एक ऐसे राष्ट्र के एकीकरण का कहीं अधिक जटिल कार्य किया, जहाँ भाषाई और सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक थी। उन्होंने कहा कि यह अद्वितीय उपलब्धि दुनिया के अन्य हिस्सों में किए गए ऐसे तुलना योग्य प्रयासों से कहीं आगे है।

उपराष्ट्रपति ने सक्षम अधिकारियों के चयन में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भूमिका की सराहना की, साथ ही उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों जैसे एचआईपीए की भी प्रशंसा की, जो सार्वजनिक सेवा के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। राष्ट्र विकसित भारत @2047 की ओर आगे बढ़ रहा है, उन्होंने अधिकारियों से भगवद गीता की भावना में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहने की सलाह दी।

सार्वजनिक सेवा में जिम्मेदार और उत्तरदायी कार्य पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति ने फाइलों और मामलों के समय पर निपटारे की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने दक्षता और सेवा अदायगी में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर बल दिया।

बातचीत के दौरान, उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक जीवन में धैर्य के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एन. जी. रंगा, श्री एन. जी. गोरे जैसे सांसदों को याद किया और उल्लेख किया कि उनका सार्वजनिक समर्थन लंबे समय तक बना रहा, जिसकी शुरूआत उनके बहसों की गुणवत्ता से हुई थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के युग में, ऊंचे स्वर में कही गयी बातें अक्सर ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन ऐसी लोकप्रियता आम तौर पर अस्थायी होती है।

भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए

ऊर्जा दक्षता लाने के लिए व्यवहार में बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (14 दिसंबर, 2025) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा संरक्षण सबसे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऊर्जा बचाना केवल कम उपयोग करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का बुद्धिमानी, जिम्मेदारी और कुशलता से उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि जब हम बिजली के उपकरणों का अनावश्यक उपयोग करने से बचते हैं, ऊर्जा-कुशल उपकरणों को अपनाते हैं, अपने घरों और कार्यस्थलों में प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं, या सौर और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को अपनाते हैं, तो हम न केवल ऊर्जा बचाते हैं बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते हैं। स्वच्छ हवा और सुरक्षित जल स्रोतों को बनाए रखने और एक संतुलित इकोसिस्टम के लिए भी ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की प्रत्येक इकाई जिसे हम बचाते हैं, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक होगी।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि यदि युवा और बच्चे ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक हों और इस दिशा में प्रयास करें, तो इस क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और देश के सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

'संवेदनशील सरकार, सुरक्षित नागरिक': गुजरात सीएमआरएफ ने 4 वर्षों में 2,106 कैंसर मरीजों को दिया नया जीवनदान

- बोनमैरो ट्रांसप्लांट सहित ब्लड कैंसर के 450 मामलोंऔरअन्य 1,656 कैंसर मरीजोंका सहारा बना CMRF
- 2021-2025 के दौरान 2,106 कैंसर रोगियों को उपचार के लिए मिली ₹31.55 करोड़ से अधिक की मदद
- लिवर, किडनी, हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण जैसे महंगे और जटिल उपचारों में भी मिलती है CMRF से वित्तीय मदद

गांधीनगर, 14 दिसंबर :गुजरात सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) संकट की घड़ी में राज्य के नागरिकों के लिए एक सशक्त सुरक्षा-कवच के रूप में उभरा है। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से लेकर गंभीर बीमारियों और जीवन-रक्षक उपचारों तक, इस कोष का दायरा लगातार विस्तृत होता जा रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सहायता के क्षेत्र में

उटफ्क्रने हजारों परिवारों को समय पर मदद, आर्थिक राहत और नई उम्मीद प्रदान की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री राहत कोष को अधिक संवेदनशील, त्वरित और जन-केन्द्रित बनाया गया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद आर्थिक तंगी के कारण उपचार से वंचित न रहे। उनकी प्राथमिकता 'लोगों का जीवन और स्वास्थ्य सर्वोपरि' के अनुरूप यह कोष आज आम नागरिकों के लिए वास्तविक सहारा और भरोसे का माध्यम बन चुका है।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन रहा CMRF

गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे मरीजों को जीवन-रक्षक चिकित्सा उपलब्ध कराना है, जिनके लिए महंगे उपचार संभव नहीं हो पाते। कैंसर, हृदय रोग, किडनी और लिवर फेल्योर, तथा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर स्थितियाँ इस सहायता के दायरे में आती हैं।

पात्रता मानदंडों के तहत आवेदक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 लाख रुपये) से कम होनी चाहिए। इसके साथ निवासी प्रमाण-पत्र, उपचार का विस्तृत अनुमान और संबंधित मेडिकल दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत सत्यापन किया जाता है। इसके पश्चात पूरी फाइल मुख्यमंत्री राहत कोष समिति के समक्ष भेजी जाती है, जिसमें राहत आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (राजस्व), मुख्य सचिव और स्वयं मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।

सम्पादकीय

कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष

नाम के अध्यक्ष! भारतीय जनता पार्टी में स्थाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पर शीर्ष नेतृत्व ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नितिन नबीन सिन्हा को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दरअसल इन दिनों भाजपा के स्थाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर काफी चर्चा है। पत्रकार भाजपा के शीर्ष नेताओं से इस संदर्भ में सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। अवसर मिलने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक से भी सवाल पूछा जा रहा है। यहां तक कि चुनाव सुधार पर संसद में हुई चर्चा के दौरान भी विपक्ष के सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठा दिया था। इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का एहसास हुआ कि इस तरफ से ध्यान भटकाने और चुनावी प्राव्रिया को लटकाने के लिए किसी नए व्यक्ति को यह दायित्व सौंप दिया जाना चाहिए। नितिन नबीन भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन किशोर सिन्हा के सुपुत्र हैं। आयु भले ही उनकी 45 वर्ष है किन्तु चार बार विधायक चुने गए हैं, इसलिए माना जाना स्वाभाविक है कि वह पार्टी की नीति, रीति और नियमों से अच्छी तरह परिचित होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष की ही बात थी और बिहार से ही बनाना था तो रविशंकर प्रासाद जैसे सांसद तो खाली ही थे किन्तु लगता है, पार्टी नेतृत्व किसी युवा को यह दायित्व सौंप कर विशेष संदेश देना चाहता था। मतलब यह कि पार्टी युवाओं को आगे लाना चाहती है। असल में जब पार्टी सत्ता में होती है तो जितने अनुभवी और योग्य नेता होते हैं, वे सभी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। यही नहीं पार्टी को भी सरकार के कामों पर निर्भर रहना होता है। यदि सरकार के कामों से लोग खुश या संतुष्ट हैं तो पार्टी का आधार बढ़ेगा और यदि नाराज हैं या उदासीन हैं तो पार्टी का बंटाधार होना तय है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ही पार्टी की नीति बनाते हैं और नियंत्रण भी यही दोनों करते हैं। ऐसे में पार्टी का अध्यक्ष जो कोई भी बनेगा उसकी भूमिका मात्र पीआरओ यानि सबसे मिलने-जुलने से ज्यादा की नहीं होगी। यही कारण है कि वैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री पार्टी का अध्यक्ष बनने को तैयार ही नहीं होता। जब कभी पार्टी हिन्दी भाषी क्षेत्रों की सीमित जनाधार वाली थी तो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव मुश्किल नहीं था। आज पार्टी का जनाधार कई अहिन्दी भाषी पश्चिम, पूवरेत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी है। इसलिए किसी युवा, व्यापक अनुभवी और अनुशासित कार्यकर्ता की जरूरत है जो मोदी, शाह और संघ नेताओं से समुचित संतुलन बनाए रखने में सफल रहे। ऐसे सर्वगुण संपन्न नेता की खोज में समय लगना स्वाभाविक है। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पैसला किया कि अभी काम चलाऊ अध्यक्ष नितिन नबीन को बना देते हैं जिन्हें बिहार में भाजपा के सभी कार्यकर्ता नहीं जानते होंगे। रही बात पार्टी के कार्यभार की तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष ही संभालते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तो मात्र नाम का ही होगा। वह न तो किसी महामंत्री, उपाध्यक्ष या नए मंत्री को संगठन में स्थान दे सकता है और न ही किसी को बाहर कर सकता है। वह मात्र संवैधानिक संस्थाओं में औपचारिकताओं को पूरा करने एवं यह दिखाने के लिए नियुक्त किए गए हैं कि अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं बल्कि नितिन नबीन हैं। कोई बड़ा पैसला न तो जेपी नड्डा ले पाते थे और न ही नितिन नबीन ले पाएंगे। मतलब कि नाम के अध्यक्ष काम के नहीं!

उप राष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया

उप राष्ट्रपति ने सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर की विरासत और मंदिरों, सिंचाई तथा तमिल साहित्य में उनके योगदान को रेखांकित किया

उप राष्ट्रपति ने तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने और तमिल के गुमनाम शासकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की और इस दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की

(जीएनएस)।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में तमिल सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर द्वितीय (सुवरण मारन) के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा तमिल संस्कृति और भाषा के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने काशी तमिल संगमम् जैसी पहलों की प्रशंसा की और उन तमिल राजाओं, नेताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान और सम्मान देने के प्रयासों की भी भूरि-भूरि सराहना की, जिन्हें पहले पर्याप्त सम्मान और मान्यता नहीं मिली थी।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर पर जारी किया गया यह स्मारक डाक टिकट तमिल विरासत को मान्यता प्रदान करने की इसी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है।

सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे प्राचीन तमिलनाडु के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक थे और वह प्रतिष्ठित मुथरैय्यर वंश से संबंध रखते थे, जिसने 7वीं से 9वीं सदी तक तमिलनाडु के केंद्रीय क्षेत्रों पर शासन किया। उन्होंने उल्लेख किया कि सम्राट ने लगभग चार दशक तक तिरुचिरापल्लि से शासन किया और उनका शासन प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार, सांस्कृतिक संरक्षण और सैन्य कौशल के कारण प्रमुख रूप से जाना जाता था।

सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर के

ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे प्राचीन तमिलनाडु के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक थे और वे उस सुप्रसिद्ध मुथरैय्यर वंश से संबंधित थे, जिसने 7वीं से 9वीं सदी सी ई काल में मध्य तमिलनाडु में शासन किया। उन्होंने यह भी बताया कि सम्राट ने लगभग चार दशक तक तिरुचिरापल्ली से शासन किया, और उनके शासनकाल को प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार, सांस्कृतिक संरक्षण और सैन्य कौशल जैसी विशेषताओं के लिए जाना जाता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि तमिलनाडु में कई स्थानों पर पाए गए शिलालेख सम्राट मुथरैय्यर के मंदिरों के लिए किए गए कार्यों, सिंचाई से जुड़ी योजनाओं और तमिल साहित्य के प्रति उनके योगदान का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सम्राट का शासन दक्षिण भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है।

ह्य2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने' के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और महान नेताओं की धरोहर का दस्तावेजीकरण, उनका सम्मान और उनकी विरासत का संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान तमिलनाडु सहित देश के सभी क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों और महान शासकों को सम्मानित करने के सरकारी प्रयासों को रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति ने यह भी बताया कि चोरी की गई लगभग 642 मूर्तियों और प्राचीन कलाकृतियों को 2014 के बाद वापस लाकर सुरक्षित किया गया है, जिनमें से कई तमिलनाडु से हैं। उप राष्ट्रपति ने इन प्रयासों को सराहनीय बताया।

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण; राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश; तथा सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

श्री संजय कुमार ने गौतम बुद्ध नगर के पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रोफॉरेस्ट का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार ने 14 दिसंबर, 2025 को पीएम श्री नवोदय विद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान 5.0 के तहत विकसित किए गए फलोद्यान एवं परागण उद्यान युक्त एक सूक्ष्म वन यानी माइक्रोफॉरेस्ट का उद्घाटन किया।

इस पहल ने मिशन लाइफ हेतु इको क्लब्स के तत्वावधान में 3,200 वर्ग मीटर से ज्यादा बंजर जमीन को जीवंत पारिस्थितिक शिक्षण स्थान में बदल दिया है। इस आयोजन में श्री राजेश लखानी, आयुक्त , नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस); डॉ.

अमरप्रीत दुग्गल, संयुक्‍त सचिव, डीएसईएल; श्री ज्ञानेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त , एनवीएस; श्रीमती वंदना तुम्मलपल्ली, सरकारी और सार्वजनिक भूमि अधिग्रहण प्रमुख, से ट्रीज; सुश्री मोनीथा, नॉलेज हेड, से ट्रीज; मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी; विद्यार्थी ; शिक्षक ; और कर्मचारी शामिल हुए।

श्री संजय कुमार ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा की असली महत्व इस बात में है कि वह प्रसन्न, मानसिक रूप से स्वस्थ और सर्वांगीण विकास वाले व्यक्तियों का पोषण करे, शिक्षण को पाठ्यपुस्तकों की सीमाओं से आगे बढ़ाकर वास्तविक जीवन के अनुभवों तक ले जाए, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में दृष्टिगत किया गया है। उन्होंने कहा कि खुशनुमा, समावेशी और प्रकृति से जुड़ा शिक्षण वातावरण विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों, सार्थक रिश्तों और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है।

पर्यावरणीय जागरूकता और अनुभवात्मक शिक्षा के संबंध में एनईपी 2020 के विजन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ हेतु इको क्लब, जो अब 9.23 लाख से ज्यादा स्कूलों में चलाए जा रहे हैं, मिशन लाइफ के सात विषयों के अनुरूप गतिविधियों के जरिए व्यावहारिक शिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों से शिक्षण को प्रकृति के साथ जोड़ने का आग्रह करते हुए स्कूल के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने एनवीएस से देश भर में साफ-सुथरे, हरे-भरे और सुव्यवस्थित परिसर विकसित करने को कहा, जहाँ मिशन लाइफ हेतु इको क्लब फल-फूल सकें तथा विद्यार्थियों की भलाई और उन्हें ज़िम्मेदार नागरिक बनाने में योगदान दे सकें।

एनवीएस के आयुक्त श्री राजेश लखानी ने विद्यालय के विद्यार्थियों से वृक्षों की देखभाल की सामूहिक ज़िम्मेदारी लेने का आग्रह करते हुए कहा कि परिसर में फलदायी वृक्षों की देखभाल करने से टिकाऊ जीवन, स्वस्‍थ आदतों और पारिस्थितिकीय संतुलन कायम करने में मदद मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से वृक्षों का पोषण और हिफाजत करते हुए नई विकसित हरी-भरी जगहों की देखभाल करने की भावना विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और उनके स्वयं के समग्र विकास में योगदान मिल सके।

विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत डीएसईएल ने स्वच्छता दक्षता और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। स्कूलों और कार्यालयों में 6.16 लाख से ज्यादा स्वच्छता अभियान चलाए गए। 9 अक्टूबर, 2025 को ई-अपशिष्ट जागरूकता और प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। उसके बाद एक ई-अपशिष्ट संग्रह अभियान चलाया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और 4,000 किग्रा से ज्यादा ई-अपशिष्ट इकट्ठा किया गया। इकट्ठा किए गए लगभग 100 किग्रा ई-अपशिष्ट का रचनात्मक तरीके से दोबारा इस्तेमाल करके नई दिल्ली के शास्त्री भवन में जागरूकता बढ़ाने वाला एक भित्ति चित्र बनाया गया।

एनवीएस गौतम बुद्ध नगर में फलोद्यान युक्त नए माइक्रोफॉरेस्ट में 500 से ज्यादा फलदायी वृक्ष हैं, जबकि परागण उद्यान में 350 से ज्यादा परागकण झअनुकूल पौधे हैं, जो मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरी जरूरी प्रजातियों के लिए पर्यावास उपलब्ध कराते हैं। इस पहल से जैव विविधता बढ़ेगी और विद्यालय परिसर के वातावरण की गुणवत्ता बेहतर होगी।

इसे गैर-लाभकारी संगठन से ट्रीज की सहायता लागू किया गया है, जिसने पूरे भारत में पाँच मिलियन से ज्यादा पेड़ लगाए हैं और 50 से ज्यादा झीलों का कायाकल्प किया है। फलोद्यान और परागण उद्यान विद्यालय परिसर का अभिन्न हिस्सा बने रहेंगे तथा एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) के अनुरूप जलवायु कार्रवाई में लगातार सहभागिता को बढ़ावा देंगे।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश भर के स्कूलों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार, स्वच्छता और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल को देश भर के दूसरे नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों और स्कूलों में भी विस्तारित किया जाएगा, जिससे पूरे देश में हरित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

आर. माधवन का बड़ा खुलासा, 'धुरंधर 2' में दिखेगा असली रणवीर सिंह, पहला पार्ट था सिर्फ ट्रेलर

(जीएनएस)।

आर. माधवन ने धुरंधर पार्ट 2 को लेकर आगे क्या होने वाला है, इसका एक बड़ा हिंट दे दिया है। ऐसे ने अब फ्रेंचाइजी में रणवीर सिंह के अगले चैप्टर को लेकर सभी की उम्मीदें अचानक काफी ज्यादा बढ़ गई हैं।रणवीर के साथ धुरंधर में स्क्रीन शेयर करने वाले आर. माधवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सीक्वल पर बात करते हुए इशारों-इशारों में कहा कि दर्शकों ने अभी रणवीर क्या लेकर आ रहे हैं, उसकी बस एक झलक ही देखी है।

कहानी को लेकर चुप्पी बनाए रखते हुए माधवन ने साफ कर दिया कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और यहां से आगे स्केल, इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस ग्राफ सिर्फ और ऊपर जाने वाला है। फैंस आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "जाहिर है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बस इतना कहूंगा कि पहला हिस्सा तो ट्रेलर था, रणवीर को अभी देखना

बाकी है।" यह बयान भले ही छोटा हो, लेकिन इसका असर बड़ा है और इसने दर्शकों के साथ-साथ इंडस्ट्री में भी उत्साह की लहर दौड़ा दी है।

धुरंधर में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को दर्शकों, क्रिटिक्स और साथी कलाकारों से जबरदस्त सराहना मिली है, और कई लोगों ने उन्हें इस पीढ़ी का सबसे बेहतरीन एक्टर तक कह दिया है। इमोशंस को सधे हुए अंदाज में दिखाने से लेकर जबरदस्त इंटेंसिटी तक, उनकी परफॉर्मेंस ने हमें गहराई से छुआ है और फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। ऐस में अब माधवन द्वारा कही गई बातें इशारा करती हैं कि धुरंधर तो सिर्फ नींव थी, जो सीक्वल में आने वाली कहीं ज्यादा ताकतवर कहानी के लिए मंच तैयार कर रही है। उनका यह हिंट बताता है कि धुरंधर 2 में रणवीर का किरदार और भी गहरे, डार्क और ज्यादा खतरनाक इलाके में जाएगा, जहां कहानी का दांव भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस के पैमाने भी।

जैसे-जैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, ऐसे में माधवन के इस कमेंट ने धुरंधर 2 को आने वाले सबसे ज्यादा इंतजार किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में खड़ा कर दिया है, खासकर रणवीर सिंह के उस किरदार के लिए जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिला है। अगर पहला पार्ट सच में सिर्फ एक "ट्रेलर" था, जैसा कि उन्होंने कहा, तो अब हम सभी रणवीर सिंह को उनके फुल फोर्स में देखने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी परफॉर्मेंस के लिए, जो एक बार फिर स्केल, इंटेंसिटी और लीडिंग मैन स्क्रीन पर क्या कर सकता है।

विशाखापट्टनम नेवी मैराथन 2025 में 17,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया

विशाखापट्टनम में जोश और उत्साह का माहौल था

(जीएनएस)।

14 दिसंबर 2025 को आयोजित विशाखापट्टनम नेवी मैराथन का 10वां संस्करण शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस आयोजन में जबरदस्त उत्साह और खेल भावना देखने को

मिली। इस प्रतिष्ठित मैराथन में 17 देशों के विदेशी नागरिकों सहित 17,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया, जिससे यह आयोजन एक नई मिसाल बन गया। 10 लाख रुपये से अधिक की इनामी राशि के साथ इस मैराथन ने देश-विदेश के खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों को एक मंच पर एकजुट किया।

फुल मैराथन (42 किमी) को हरी झंडी दिखाने और पुरस्कार वितरण समारोह की शोभा वाइस एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड ने बढ़ाई। हाफ मैराथन और संकल्प रन को श्रीमती प्रिया भल्ला, अध्यक्ष, एनडब्ल्यूडब्ल्यूए (पूर्वी क्षेत्र) ने हरी झंडी दिखाकर उद्देश्य, एकता और सामुदायिक सहभागिता की भावना को मजबूत किया। 10 किमी दौड़ को जिला कलेक्टर तथा 5 किमी दौड़ को पुलिस आयुक्त ने हरी झंडी दिखाई। इस भव्य आयोजन में फ्लैग ऑफिसर्स, जीवीएमसी आयुक्त, वरिष्ठ पूर्व सैनिकों तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) जैसे प्रमुख साझेदारों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई।

बारीक प्लानिंग और बिना किसी रुकावट के एग्जीक्यूशन ने सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक शानदार अनुभव पक्का किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी पुलिस और लोकल कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिला।

इस एडिशन में कई नए और बेहतर फीचर्स पेश किए गए, जिसमें रनर्स के लिए आकर्षक डिस्काउंट और डिलीवरेबल्स का एक बेहतर पैकेज शामिल था। इसके अलावा, सभी पार्टिसिपेंट्स को इंश्योरेंस कवर भी दिया गया, जिससे पूरे इवेंट के दौरान उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित हुई।

अपनी बढ़ती पहचान को दिखाते हुए, इस मैराथन में विदेशी देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिससे इसकी बढ़ती इंटरनेशनल अपील साबित हुई और यह इस क्षेत्र की प्रमुख मैराथनों में से एक के रूप में मजबूती से स्थापित हो गई।

विशाखापट्टनम नेवी मैराथन 2025 इसमें शामिल सभी लोगों के समर्पण, टीम वर्क और जुनून का सबूत थी। यह इवेंट आने वाले सालों में और ज्यादा तरक्की के लिए तैयार है। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों, सभी धावकों और आयोजकों को दिल से शुभकामनाएं दीं और इस इवेंट को जबरदस्त सफल बनाने में उनके समर्थन और भागीदारी के लिए जिला प्रशासन, शहर पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों का आभार व्यक्त किया।

क्या बंद हो जाएगा इन लाड़ली बहनों का पैसा! मंत्री की धमकी से लाभार्थियों में मचा हड़कंप

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार निशाने पर हैं अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री डॉ. विजय शाह, जिन्होंने राज्य की हजारों 'लाड़ली बहनों' को सीधे तौर पर एक चौंकाने वाली धमकी दे डाली है।

शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर योजना की लाभार्थी महिलाएं मुख्यमंत्री का 'सम्मान' करने कार्यक्रमों में नहीं आती हैं, तो उनकी पात्रता की गहन जांच की जाएगी और भुगतान रोक दिया जाएगा!

क्या यह धमकी लाखों महिलाओं के बीच डर पैदा कर रही है कि कहीं मंत्री जी की नाराजगी उनकी मासिक किश्त को पेंडिंग न कर दे? या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक बयानबाजी है? जानिए इस पूरे मामले पर क्यों गरमाई है प्रदेश की सियासत...

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों को चेतावनी दी है। मंत्री डॉ. विजय शाह शनिवार को रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुए थे। इसी दौरान, उन्होंने एक धमकी भरे लहजे में कहा, 'सरकार अगर करोड़ों रुपए दे रही है, तो लाड़ली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएंगी, उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी।'

मंत्री के इस बयान के तुरंत बाद, राज्य की सियासत गरमा गई है और विपक्षी कांग्रेस ने सरकार और मंत्री पर तीखा हमला बोला है।

भुगतान और आधार लिंकिंग पर भी टिप्पणी

बैठक के दौरान, मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों की संख्या पूछी, तो उन्हें बताया गया कि जिले में लगभग ढाई लाख लाड़ली बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस पर, मंत्री शाह ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री को दो साल हो गए हैं और सरकार ₹1500 दे रही है, तो एक धन्यवाद तो बनता है।

उन्होंने आगे कहा कि जिन बहनों को बढ़े हुए ₹250 मिल रहे हैं, उनकी जांच की जाएगी कि वे आधार से लिंक हैं या नहीं। यदि वे लिंक नहीं हैं, तो उनका पैसा पेंडिंग कर दिया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि मंत्री विजय शाह का विवादों से पुराना नाता रहा है।

इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आईं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। विवाद बढ़ने के बाद, उन्होंने बाद में माफी मांगते हुए कहा था कि कर्नल सोफिया कुरैशी उनकी सगी बहन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था, 'अगर उत्साह में कुछ निकल गया और किसी को ठेस पहुंची, तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। एक बार नहीं, मैं दस बार माफी मांगता हूं।'

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र में 'सांसद खेल महोत्सव' के समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को इस भव्य आयोजन को आभासी रूप से संबोधित करेंगे

सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह का समन्‍वय संबंधित विधायक और सांसद करेंगे

25 दिसंबर को देश भर में 'सांसद खेल महोत्सव' के समापन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आभासी समन्वय बैठक हुई

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर-कठुआ-डोडा लोकसभा क्षेत्र के उपायुक्तों (डीसी) और विधायकों (एमएलए) के साथ आभासी बैठक की। इस बैठक में 25 दिसंबर 2025 को होने वाले सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में समापन समारोह का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के बीच सुचारु समन्‍वय पर ध्‍यान केंद्रित किया गया। समापन समारोह को प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आभासी रूप से संबोधित करेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 25 दिसंबर को होने वाला समापन समारोह सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन, विधायक और सांसद सक्रिय रूप से शामिल होंगे। यह 25 अगस्त 2025 को शुरू हुए सांसद खेल महोत्सव का सफल समापन होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कार्यक्रम को पूरे भारत में, बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है, जिसका

उद्देश्‍य फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट, स्वस्थ और खेल-उन्मुख भारत के विजन को मजबूती प्रदान करते हुए जमीनी स्तर की खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करना है।

डॉ. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सभी ज़िलों को अंतिम निदेर्शों के अनुरूप, ज़िला-स्तर और निर्वाचन क्षेत्र-स्तर की भागीदारी सहित विविध कार्यान्वयन मॉडलों के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के आभासी संबोधन को ध्यान में रखते हुए पुख्‍ता कनेक्टिविटी और समुचित बुनियादी सुविधा वाली सही जगहों की पहचान करने का निर्देश दिया।

सांसद खेल महोत्सव के दीर्घकालिक विजन पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल सिर्फ.एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरे देश में खेल से संबंधित टिकाऊ इकोसिस्टम तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने पंचायत, ब्लॉक, ज़िला और उच्च स्तर पर विजेताओं का विवरण निर्धारित पोर्टल पर समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया ताकि होनहार एथलीटों की पहचान की जा सके, उनकी सहायता की जा सके और उन्हें उन्नत प्रशिक्षण, अनुभव और भविष्य में उच्च प्रतिस्पर्धी मंचों पर हिस्सा लेने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

डॉ. सिंह ने इस बात की ओर भी इंगित किया कि समापन समारोह का आयोजन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के साथ हो रहा है, जो शासन, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र-निर्माण के विषयों को जोड़ने का अवसर देता है। उन्होंने लोगों तक पहुँच और विज़िबिलिटी बढ़ाने के लिए जिलों को इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी गई कि समापन समारोह में स्थानीय युवा, खिलाड़ी, समुदाय के प्रतिनिधि और खेल जगत की जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी। ये कार्यक्रम लोगों तक व्यापक पहुँच और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए "माई भारत" प्लेटफॉर्म के बड़े फ्रेमवर्क के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा जिला प्रशासन की सहायता से आयोजित किए जाएंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सभी हितधारकों से मिलकर काम करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि सांसद खेल महोत्सव का समापन एक आदर्श राष्ट्रीय आयोजन के तौर पर हो, जो खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूत करने के सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही और विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी स्तरों पर समय पर तैयारी किए जाने की आवश्यकता दोहरायी।

एमएसएमई को समर्थन देने के लिए बीआईएस द्वारा वार्षिक न्यूनतम अंकन शुल्क में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया

सरकार घरेलू उत्पादन में कोई व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई के लिए छूट और रियायतें के साथ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लागू करती है

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मौद्रिक नीति संचरण में सुधार के लिए एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों को बाहरी मानकों से जोड़ने की सलाह दी है

(जीएनएस)। भारत सरकार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से एमएसएमई के लिए छूट/छूट के साथ संबंधित मंत्रालयों द्वारा चरण-वार, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को लागू करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) घरेलू उत्पादन को बाधित न करें। कुछ प्रमुख छूट और रियायतें इस प्रकार हैं:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए अतिरिक्त समय: सूक्ष्म उद्यमों के लिए 6 महीने का विस्तार और लघु उद्यमों के लिए 3 महीने का विस्तार।

नियातीन्मुखी उत्पादों के उत्पादन के लिए घरेलू निमार्ताओं द्वारा आयात पर छूट।

अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए 200 इकाइयों तक के आयात पर छूट।

लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर पुराने स्टॉक (कार्यान्वयन से पहले निर्मित या आयातित) को निपटाने का प्रावधान।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सूचित किया है कि प्रमाणन प्रक्रियाओं पर प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, बीआईएस ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वित्तीय और तकनीकी छूट लागू की हैं:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को सहयोग देने के

लिए, बीआईएस द्वारा वार्षिक न्यूनतम विपणन शुल्क में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म उद्यमों के लिए 80 प्रतिशत, लघु उद्यमों के लिए 50 प्रतिशत और मध्यम उद्यमों के लिए 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में स्थित उद्यमों या महिला उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसएमई इकाइयों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए आंतरिक प्रयोगशाला बनाए रखने की अनिवार्यता को वैकल्पिक कर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाओं, एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाएं ले सकती हैं या क्लस्टर आधारित प्रयोगशालाओं या अन्य विनिर्माण इकाइयों की प्रयोगशालाओं जैसे संसाधनों को साझा कर सकती हैं। निरीक्षण एवं परीक्षण योजना (एसआईटी) में ह्यनियंत्रण स्तर' को केवल अनुशंसात्मक बनाया गया है। निमार्ता के पास अपनी नियंत्रण इकाई/बैच/लॉट और अपने नियंत्रण स्तर निर्धारित करने और बीआईएस को सूचित करने का विकल्प है।

बीआईएस ने उत्पाद प्रमाणीकरण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश भी बीआईएस वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिए हैं। बीआईएस विभिन्न भारतीय मानकों के अनुरूपता मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शन दस्तावेजों के रूप में उत्पाद-वार नियमावली भी जारी कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मौद्रिक नीति के संचरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, बैंकों को एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी गई है। बाहरी बेंचमार्क प्रणाली के तहत ऋणों के लिए रीसेट क्लॉज को घटाकर तीन महीने कर दिया गया है। इसके अलावा, मौजूदा उधारकताओं को बाहरी बेंचमार्क-आधारित ब्याज व्यवस्था का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, बैंकों को आपसी सहमति के अनुसार स्विचओवर विकल्प प्रदान करने की सलाह दी गई है। साथ ही, आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) की घोषणा की है। यह सरकारी पहल एमएसएमई को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बनाई गई है। यह योजना ऋण गारंटी प्रदान करती है, जिससे एमएसएमई के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है, विशेष रूप से आवश्यक उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए। यह योजना एमएसएमई को उपकरण/मशीनरी की खरीद से संबंधित परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋणों के लिए ऋणदाताओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, गैर-वित्तीय वित्तीय संस्थान) को ऋण गारंटी प्रदान करती है।

प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार न करने का आदेश दिया गया है।

एमएसई इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की गणना 5 करोड़ रुपये तक की उधार सीमा के लिए अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (सुश्री शोभा करंदलाजे) ने यह जानकारी लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

भारत का रेल विद्युतीकरण अभियान पूरा होने के करीब, शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य और स्वच्छ एवं त्वरित यात्री परिवहन को संभव बनाएगा

भारत के रेल विद्युतीकरण से दक्षता में वृद्धि, डीजल की खपत में कमी और वैश्विक स्तर पर एक नया मानक स्थापित हुआ है

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे अपने लगभग पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण को पूरा करने के करीब है और 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पहले ही विद्युतीकृत हो चुका है तथा शेष हिस्सों का काम भी शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। हाल के वर्षों में काम की गति असाधारण रही है। वर्ष 2019 से 2025 के बीच, भारतीय रेलवे ने 33,000 किलोमीटर से अधिक मार्ग का विद्युतीकरण किया, जो औसतन प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक की गति से हुआ है। इस अवधि के दौरान विद्युतीकृत कुल दूरी लगभग जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है, जो स्वच्छ और कुशल रेल परिवहन के विस्तार में भारत की व्यापकता और गंभीरता को दशार्ता है।

भारत का ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क लगभग पूरी तरह से विद्युतीकृत है, जो 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.2 प्रतिशत तक फैला हुआ है।

भारत की उपलब्धि उन देशों की तुलना में भी उल्लेखनीय है जिनके पास लंबे समय से स्थापित रेल प्रणालियाँ हैं। दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक का संचालन करते हुए भी, भारत ने अपनी लगभग पूरे ब्रॉड-गेज प्रणाली का विद्युतीकरण कर लिया है।

इस परिवर्तन से डीजल की खपत कम हुई है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, परिचालन लागत घटी है और रेलगाड़ी संचालन की दक्षता और गति में सुधार हुआ है। जहाँ कई विकसित अर्थव्यवस्थाएँ लागत या संरचनात्मक सीमाओं के कारण अब भी डीजल पर बहुत अधिक निर्भर हैं, वहीं भारत ने स्पष्ट योजना और निरंतर कार्यान्वयन के साथ आगे कदम बढ़ाया है।

जैसे-जैसे अंतिम चरण पूरे हो रहे हैं, देश दुनिया के सबसे बड़े पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे प्रणाली में से एक का संचालन करने के लिए तैयार है। यह भारतीय रेलवे के शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लक्ष्य का समर्थन करता है और प्रतिदिन लाखों यात्रियों को स्वच्छ, तेज और अधिक विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के उड़न दस्ते ने दिल्ली में डीडीए के रखरखाव वाले 136 सड़क खण्डों का निरिक्षण किया

संबंधित सड़क खण्डों के रखरखाव में प्रत्यक्ष कमियों को उजागर किया

आयोग ने निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर डीडीए को अनुकूल और समय पर धूल कम करने के उपायों को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया

(जीएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 12 दिसंबर 2025 को सड़क निरीक्षण अभियान के लिए 19 टीमें तैनात कीं। इस अभियान के तहत, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल 136 सड़क खंडों का निरीक्षण पूरी दिल्ली में किया गया। यह निरीक्षण आयोग के वैधानिक ढाँचे और वर्तमान में लागू जीआरएपी के प्रावधानों के तहत निरंतर निगरानी रखने और उन्हें व्यवहार में लाने के प्रयासों के लिए किया गया था।

इन उपायों का उद्देश्य सड़क खंडों पर दिखने वाली धूल, नगरपालिका द्वारा फेंके जाने वाले कूड़े और भवन निर्माण और उन्हें तोड़े जाने से पैदा होने वाले मलबे के ढेर का आकलन करना था। साथ ही सड़कों पर नगरपालिका द्वारा जैविक कचरे को खुले में जलाने से जुड़े मामलों की भी जाँच की गई। तैनात की गई टीमों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के उड़न दस्ते और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी शामिल थे।

निरीक्षण रिपोर्ट में जियो-टैग और समय पर ली गईं तस्वीरें आयोग के सामने पेश की गईं। अंतिम संकलित आंकड़ों के अनुसार, 15 सड़क खंडों में धूल का उच्च स्तर दिखाई दिया, 38 में मध्यम धूल दिखाई दी, 61 में कम धूल और 22 खंडों में बिलकुल धूल नहीं पाई गई। नगरपालिका के कूड़े वाले 55 और भवन निर्माण और उन्हें तोड़े जाने से पैदा होने वाले मलबे के ढेर वाले 53 सड़क खण्डों की रिपोर्ट दर्ज की गई। 6 सड़क खण्डों पर नगरपालिका द्वारा कूड़े और जैविक कचरे को जलाने के प्रमाण मिलने की सूचना प्राप्त हुई।

निरिक्षण से संबंधित सड़क खंडों के रखरखाव में स्पष्ट कमियों और बार-बार होने वाली लापरवाही का पता चलता है। इससे डीडीए को अपनी परिचालन कुशलता बढ़ाने और समय पर धूल कम करने जैसे तत्काल किये जाने वाले सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता उजागर हुई। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि एजेंसी को जैविक कचरा जलाने के संबंध में सभी सड़क खंडों पर बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

आयोग ने पाया कि इस प्रकार की घटनाएँ दिल्ली में कण प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती हैं, और इसके साथ ही आयोग ने डीडीए द्वारा रखरखाव वाले सभी सड़क खंडों पर जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें नियमित रूप से मशीनीकृत सफाई सुनिश्चित करना, इकठ्ठा की गई धूल को समय पर उचित तरीके से निपटाना, सड़क के किनारों और डिवाइडरों का उचित रखरखाव करना, धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव करना और जैविक कचरे को जलाने के मामलों को कम करना या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है।

आयोग ने दोहराया कि 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत इस तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि धूल नियंत्रण और जैविक कचरे को खुले में जलाने से संबंधित मामलों को कम करने के लिए उसके वैधानिक निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसका उद्देश्य पूरी दिल्ली को स्वच्छ, धूल और खुले में जलाने से मुक्त करना और नियामक उपायों के अनुरूप रखना है।

आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक प्रयास: भारतीय रेलवे ने 11 सालों में 42,600 से अधिक एलएचबी कोचों का निर्माण किया

एलएचबी कोचों से रेल यात्रा अधिक सुरक्षित, सुगम और कुशल बनती है

भारतीय रेलवे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' को मजबूत कर रहा है

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे ने लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोचों के उत्पादन में लगातार प्रगति की है, जिन्हें यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा, बेहतर यात्रा आराम और बेहतर परिचालन प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान कुल 4,224 से अधिक एलएचबी कोचों का निर्माण किया गया है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में उत्पादित 3,590 कोचों की तुलना में 18% की वृद्धि दशार्ता है। उत्पादन में यह वृद्धि रेलवे इकाइयों में विनिर्माण क्षमता के निरंतर सुदृढ़ीकरण और बेहतर उत्पादन नियोजन को प्रदर्शित करती है।

इस अवधि के दौरान कारखानेवार प्रदर्शन की बात करें तो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई ने 1,659 एलएचबी कोचों का उत्पादन किया है, इसके बाद मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ), रायबरेली ने 1,234 कोचों का और रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ), कपूरथला ने 1,331 कोचों का उत्पादन किया है। इन सभी ने मिलकर एलएचबी कोच उत्पादन में समग्र वृद्धि में योगदान दिया है।

दीर्घकालिक तुलना की जाए तो हाल के वर्षों में हासिल की गई उल्लेखनीय

प्रगति साफ दिखाई देती है। 2014 और 2025 के बीच, भारतीय रेलवे ने 42,600 से अधिक एलएचबी कोचों का उत्पादन किया, जो 2004 और 2014 के बीच निर्मित 2,300 कोचों की तुलना में 18 गुना अधिक है। यह विस्तार एलएचबी कोचों को व्यापक रूप से अपनाकर यात्री परिवहन को आधुनिक बनाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है, जो अपने बेहतर सुरक्षा मानकों और कम रखरखाव की जरुरतों के लिए जाने जाते हैं।

घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर और आयात पर निर्भरता कम करके भारतीय रेलवे, 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के लक्ष्यों में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यह संगठन देश की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने और यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने पर केंद्रित है।

श्री सबार्नंद सोनोवाल जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की यात्रा से पहलफर्टिलाइजर परियोजना के लॉन्च की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नामरूप का दौरा किया

"पीएम मोदी जी की नामरूप फर्टिलाइजर परियोजना असम के लिए नए औद्योगिक दौर का संकेत है": श्री सबार्नंद सोनोवाल

(जीएनएस)। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) श्री सबार्नंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ जिले में नामरूप फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जिससे 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की तय यात्रा से पहले जमीनी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी नामरूप में चौथे फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखेंगे।

नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के मौजूदा परिसर में ₹10,000 करोड़ से अधिक के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को असम के औद्योगिक आधार को मजबूत करने और पूरे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में उर्वरक की उपलब्धता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

साइट पर दौरे के दौरान, श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए लॉजिस्टिक्स इंतजाम, सुरक्षा तैयारियों और कुल मिलाकर सारी तैयारियों का जायजा लिया।

सोनोवाल ने शुरूआती कामों की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया, जिससे यह पक्का हो सके कि शिलान्यास समारोह की सभी तैयारियां आसानी से और समय पर पूरी हो जाएं।

सोनोवाल जी ने कहा, "यह परियोजना असम के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करती है," और बताया कि नामरूप में चौथे प्लांट की मांग दशकों से की जा रही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का इस परियोजना को शुरू करने का फैसला पूर्वोत्तर के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता और भारत के कृषि और औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के वादे को प्रतिबिंबित करता है।

श्री सबार्नंद सोनोवाल ने जगह की समीक्षा के बाद कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में, असम के लोगों की दशकों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। नामरूप में चौथा फर्टिलाइजर प्लांट पूर्वोत्तर के प्रति प्रधानमंत्री जी की गहरी प्रतिबद्धता और भारत की कृषि और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उनके संकल्प को दिखाता है।"

अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक बार शुरू होने के बाद, नई फर्टिलाइजर इकाई से पूर्वोत्तर में यूरिया और संबंधित उत्पादों की सप्लाई चेन में काफी विस्तार होने की उम्मीद है, जिससे दूर के उत्पादन केंद्रों पर निर्भरता कम होगी और किसानों को समय पर उपलब्धता बेहतर होगी। इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता लगभग 1.25 मिलियन मीट्रिक टन होगी और इससे काफी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण की उम्मीद है।

सबार्नंद सोनोवाल जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर में हो रहे बड़े विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षमता में बड़े निवेश का जिक्र किया, जिससे पूरे इलाके में युवाओं, किसानों और मजदूरों के लिए नए मौके बने हैं।

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री जी के साथ राज्य के वरिष्ठ मंत्री, स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी और नागरिक और विकास निकायों के प्रतिनिधि मौजूद थे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आपस में तालमेल बनाकर काम करें, जिससे प्रधानमंत्री जी का दौरा और शिलान्यास समारोह सफलतापूर्वक पूरा हो सके।

केंद्रीय मंत्री जी ने साइट पर अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद कहा, "21 दिसंबर को नामरूप में प्रधानमंत्री जी का दौरा असम के लिए गर्व का पल है। हम पूरी लगन से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि शिलान्यास समारोह बिना किसी कमी के हो, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के बदलाव लाने वाले विकास एजेंडा और पूर्वोत्तर पर उनके खास ध्यान को प्रदर्शित करे।"

उम्मीद है कि नामरूप प्रोजेक्ट असम की औद्योगिक प्रगति में एक नया अध्याय शुरू करेगा, पूर्वोत्तर के लिए फर्टिलाइजर सुरक्षा को मजबूत करेगा और कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देगा।

केंद्रीय मंत्री श्री सबार्नंद सोनोवाल के साथ अन्य अधिकारियों के बीच असम सरकार में मंत्री प्रशांत फुकन और जोगेन मोहन; विधायक तरंगा गोगोई, बिनोद हजारिका, चक्रधर गोगोई, तेराश गोवाला, भास्कर शर्मा और धर्मेश्वर कोंवर; असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी), अध्यक्ष, रितुपर्णा बरुआ; डिब्रूगढ़ नगर निगम (डीएमसी), महापौर, सैकत पात्रा और उप महापौर, उज्ज्वल फुकन; डिब्रूगढ़ विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष, असीम हजारिका; सोनोवाल कचारी स्वायत्त परिषद (एसकेएसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य, टंकेश्वर सोनोवाल; और उपायुक्त बिक्रम कैरी भी उपस्थित थे।

'बीजेपी कार्यकर्ता जुट जाएं', सीएम योगी बोले- एसआईआर में 12 दिन बेहद महत्वपूर्ण, बेहतर करिए उपयोग

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं को जुटने का आ'ान किया है। कहा कि अब केवल 12 दिन शेष बचे हैं इसका बेहतर उपयोग करिए।

चुनाव का परिणाम विधान सभा व लोक सभा में आता है, लेकिन चुनाव बूथ पर ही लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ह्यमेरा बूथ-सबसे मजबूत' यानी लड़ाई बूथ पर होती है, इसलिए वह सबसे मजबूत होना चाहिए।

हर बूथ पर औसतन पौने दो सौ से ढाई सौ नाम ऐसे हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत व डुप्लीकेट हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर शक्ति केंद्र के पदाधिकारी एक साथ मिलकर अपने बूथ पर मतदाता सूची के नामों का अवलोकन कर लें।

संगठन पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को एक किस्सा सुनाया। कहा कि एक जिले के दौरे पर जब वह गए तो वहां की मतदाता सूची में उन्हें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम भी मिले।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक जिले में ऐसा फार्म भरा गया, जहां मतदाता की आयु 20, पिता की 30 वर्ष और बाबा की आयु 40 साल है। फर्जी नाम का उदाहरण दिया और बताया कि रहने वाले असम के हैं, लेकिन मतदाता संभल में बने हुए हैं। कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ से

फर्जी नाम पर आपत्ति दर्ज कराइए। नाम जोड़ने व काटने के लिए अभी 12 दिन का समय है।

मुख्यमंत्री ने एसआइआर में कार्यकर्ताओं को मेहनत से काम करने के लिए कहा है। बोले आपकी तीन चौथाई मेहनत अभी हो जाएगी तो विधान सभा चुनाव में सिर्फ एक चौथाई मेहनत ही करनी पड़ेगी। प्रदेश में तीन चौथाई सीट भाजपा व गठबंधन प्रत्याशी जीत लेंगे।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने बूथ को सबसे मजबूत कीजिए। एसआइआर के जो प्रपत्र जमा नहीं हो पाए, युद्ध स्तर पर लगकर उन्हें जमा कराइए। नए मतदाताओं को फार्म-6 भरवाइए। हर बूथ की समीक्षा व मेहनत ही परिणाम लाएगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए कहा कि जब भी उनसे सहयोग मांगा, तब उन्होंने यूपी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। एक जिला एक उत्पाद के लिए हमने पैकेजिंग इंस्टीटयूट मांगा तो लखनऊ में भारत सरकार ने इसे स्वीकृति दी। इसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है।

वे अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, इसलिए नहीं देते थे बिजली

मुख्यमंत्री ने सपा को घेरते हुए कहा कि 2017 के पहले जिन हाथों में कमान थी, वे अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, वे बिजली नहीं देते थे, क्योंकि डकैती अंधेरे में ही पड़ती थी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार आने के बाद अप्रैल 2017 से बिजली का जो रोस्टर तय किया, वह आज भी प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है।

लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में मानवीय सेवा का उदाहरण - बृज की रसोई का व्यापक भोजन वितरण

सैकड़ों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान - बृज की रसोई की निःशुल्क भोजन सेवाः विपिन शर्मा

आशियाना, लखनऊ (उ.प्र.) दिनांक : 14 दिसम्बर 2025: प्रेरणाश्रोत बाबा नीम करौली जी की कृपा से इण्डियन हेल्पलाइन सोसाइटी (रजि.) द्वारा संचालित बृज की रसोई के अंतर्गत आज आशियाना क्षेत्र में निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

संस्था के संस्थापक विपिन शर्मा ने अवगत कराया आज रविवार सायं 03 बजे से प्रारंभ हुई इस सेवा गतिविधि में बड़ी संख्या में बच्चों, बुजुर्गों तथा जरूरतमंद परिवारों ने सहभागिता की। संस्था के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों ने अत्यंत अनुशासित एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ भोजन वितरण कार्य किया। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लाभार्थियों को स्वच्छ एवं सुपाच्य भोजन उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दी।

विशाल सक्सेना ने बताया कि अन्नदान भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च मानवीय महत्व रखता है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए बृज की रसोई प्रत्येक रविवार को आशियाना क्षेत्र में भोजन सेवा का नियमित संचालन करती है।

वहीं विकास पाण्डेय ने कहा संस्था का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक सम्मानजनक सहायता और सहयोग पहुँचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए।

आशीष श्रीवास्तव ने बताया कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, समाजसेवी सहयोगियों तथा युवा स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर यह संदेश दिया कि सामाजिक जिम्मेदारी सामूहिक प्रयासों से ही अधिक प्रभावी बनती है।

अनुराग दुबे ने सभी सहयोगकताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि जनसहभागिता ही इस सेवा प्रकल्प की वास्तविक शक्ति है।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने बताया संस्था ने यह भी अवगत कराया कि यदि इच्छुक लोग इस पुनीत कार्य से जुड़ना चाहते हैं, तो वे प्रत्यक्ष सेवा में भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

दीपक भुटियानी ने जानकारी दी कि आज का निःशुल्क भोजन वितरण सेक्टरझ्रएम रिक्शा कॉलोनी, रतन खंड पार्क, डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पास स्थित झुग्गीझ्र झोपड़ियाँ, निमार्णाधीन भवनों में कार्यरत श्रमिकों के अस्थायी आवास, नगर निगम जोनझ्र8 की मलिन बस्तियाँ तथा रतनखंड पानी टंकी सहित अनेक क्षेत्रों में संपन्न हुआ। इस दौरान लगभग 1550 निराश्रित, असहाय एवं जरूरतमंदों को सप्रेम भोजन राजमा चावल एवं गाजर का हलुआ परोसा गया।

आज के कार्यक्रम में संस्था के समर्पित पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक दीपक भुटियानी, विशाल सक्सेना, अनुराग दुबे, आशीष श्रीवास्तव, विकास पाण्डेय, नवल सिंह, मुकेश कनौजिया, दिनेश पाण्डेय, ध्रुव सक्सेना एवं गोविन्द सिंह ठाकुर सहित अनेक समाजसेवियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम शांति, अनुशासन और सेवा-भाव के साथ सम्पन्न हुआ।

दो साल से अधूरा पड़ा 'हर घर नल जल' कार्यः खोदी सड़कें बनीं मुसीबत

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पूरनपुर तहसील के दौलतपुर गांव में 'हर घर नल जल योजना' के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य पिछले दो वर्षों से अधूरा पड़ा है। जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश के दौरान जलभराव और कीचड़ ने आवागमन को जटिल बना दिया है, जबकि लाखों रुपये की सीसी सड़कें खराब हो रही हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने पाइपलाइन डालने के लिए गांव की प्रमुख सड़कों को खोद तो दिया, लेकिन कार्य पूरा न होने पर मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की। जगह-जगह लीकेज से सड़कें टूटी-फूटी हो गई हैं, जिससे वाहन चालकों व पैदल यात्रियों को दिक्कत हो रही। एक ग्रामीण ने बताया, "बारिश में तो कीचड़ से गुजरना नामुमकिन हो जाता है, और सीसी रोड भी अब गड्ढों से भर गई।"

जल जीवन मिशन के तहत शुरू यह प्रोजेक्ट दो साल से ज्यादा चले,अब देखना होगा कि जल निगम कब तक इस लापरवाही को सुधारता है।

गन्ना केंद्र पर अवैध उतराई वसूली का मामलाः प्रति ट्रॉली 100 रुपये ले रहे अधिकारी, किसान चार दिनों से धरने पर

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पूरनपुर के सुल्तानपुर गन्ना क्रय केंद्र पर तोल के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां किसानों से प्रति ट्रॉली 100 रुपये तक उतराई शुल्क लिया जा रहा। जिला गन्ना अधिकारी के स्पष्ट आदेशों के बावजूद यह मनमानी जारी है, जिससे किसानों में गहरा असंतोष फैल गया। आक्रोशित किसानों ने चार दिनों से तोल रुकवा रखी है और धरना प्रदर्शन शुरू कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

किसानों का आरोप है कि गन्ना इंचार्ज की मनमानी से प्रति ट्रॉली 50 किलो गन्ना के बराबर अवैध वसूली हो रही। एक किसान ने बताया, "हमारे गन्ने की तोल चार दिनों से नहीं हो रही, जबकि शुल्क न देने पर ट्रॉली ही नहीं उतारने दी जाती। यह सरासर शोषण है।" पीलीभीत के कई अन्य केंद्रों पर भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जहां उतराई के नाम पर 100 रुपये प्रति ट्रॉली वसूले जा रहे। जिला गन्ना अधिकारी ने वसूली रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा।

किसानों की प्रमुख मांगें

- अवैध उतराई शुल्क पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
- गन्ना तोल प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

धरना स्थल पर दर्जनों किसान जमा हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नारेबाजी कर रहे। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया है कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं। यदि वसूली न रुकी तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई

4 जीवित लोगों को मृत घोषित कर राशन कार्ड से काटे नाम, पीड़ितों ने विभाग से लगाई न्याय की गुहार

(जीएनएस)।

पीलीभीतः बीसलपुर ब्लॉक के रिछोला सबल गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो परिवारों के चार जीवित सदस्यों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उनके राशन कार्ड से नाम हटा दिए गए। बिना किसी मृत्यु प्रमाण पत्र के यह कार्रवाई होने से पीड़ित परिवारों में रोष है, और वे अब अधिकारियों से नाम बहाली की मांग कर रहे हैं।

पीड़ितों में लईक अहमद का परिवार प्रमुख है, जिन्होंने राशन लेने दुकान पर जाने पर कोटेदार से जाना कि उनके कार्ड की चार यूनिट निरस्त हो गईं। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि परिवार के चार सदस्यों को मृत दिखाकर नाम काट दिए गए, जबकि सभी जीवित हैं। इसी गांव के अशफाक हुसैन और उनके बेटे के साथ भी यही समस्या हुई। लईक अहमद ने बताया, "हम जीवित हैं, फिर भी राशन से वंचित कर दिया गया। यह विभागीय लापरवाही है।"

नियमों के अनुसार, राशन कार्ड से किसी का नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है, लेकिन यहां बिना दस्तावेज के ही नाम काटे गए। पीड़ित परिवार अब तहसील व खाद्य विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, ताकि उनकी पहचान साबित कर नाम दोबारा जुड़वाए जा सकें। ग्राम प्रधान ने भी मामले को संज्ञान में ले लिया है।

इस घटना से गांव में चर्चा का विषय बना है कि सरकारी योजनाओं में ऐसी त्रुटियां कैसे हो रही हैं। विभाग ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन जांच के संकेत दिए गए हैं।

सेहरामऊ उत्तरी थाने के महिला सुरक्षा केंद्र ने सुलझाया दांपत्य विवादः काउंसलिंग से बनी सहमति

(जीएनएस)।

पीलीभीत,सेहरामऊ उत्तरी स्थित महिला सुरक्षा केंद्र की पहल से एक दंपति का लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक विवाद सुलझ गया। काउंसलिंग सत्र के बाद पति-पत्नी के बीच सहमति बनी, और उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लिया। इस सराहनीय प्रयास से न केवल एक परिवार टूटने से बचा, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी फैला।

मामला ग्राम सेहरामऊ उत्तरी निवासी रेशमा देवी की 8 दिसंबर को दर्ज शिकायत से जुड़ा है। रेशमा ने बताया कि उनकी बेटी सीमा देवी के पति सुगम (पलिया, लखीमपुर खीरी निवासी) शादी के डेढ़ वर्ष बाद भी सीमा को अपने साथ रखने से इनकार कर रहे थे। इससे पति-पत्नी के बीच गहरे मतभेद हो गए थे।

शिकायत मिलते ही महिला सुरक्षा केंद्र ने सक्रियता दिखाई और 14 दिसंबर को दोनों पक्षों को थाने बुलाया। केंद्र की पुलिस टीम ने धैर्यपूर्वक काउंसलिंग की, पारिवारिक जीवन के महत्व और जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। सत्र में दोनों ने अपनी बातें रखीं, जिसके बाद सहमति बनी। अंत में, पति-पत्नी ने मतभेद भुलाकर एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और सुखी दांपत्य जीवन का वादा किया। थाने से उन्हें एक साथ विदा किया गया।

स्थानीय लोगों ने महिला सुरक्षा केंद्र की इस पहल की खूब तारीफ की। एक ग्रामीण ने कहा, "ऐसे प्रयासों से कई परिवार बच सकते हैं।"

झूंसी में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों लोगों ने लिया लाभ

(जीएनएस)।

श्री रामलखन चैरिटेबल ट्रस्ट, झूंसी द्वारा रविवार, 14 दिसंबर को आयोजन स्थल झ्र भोजपुर (सत्संग भवन कैम्पस), आवास संख्या 89, मंगनापुर चौराहा, रिंग रोड, झूंसी, प्रयागराज। में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य जांच, परामर्श एवं निःशुल्क दवाइयों का लाभ लिया।

कार्यक्रम की शुरूआत वैदिक हवन-यज्ञ से हुई, इसके बाद निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एलोपैथी, होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच की गई। आंखों की जांच के दौरान निःशुल्क चश्मा वितरण एवं चिन्हित मरीजों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु उन्हें वासुदेव हॉस्पिटल, झूंसी भेजा गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माङ्क गणेश केसरीवानी (महापौर, प्रयागराज) की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों ने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से रामबाबू गुप्ता (मद्रासी), राजीव गुप्ता, शोभित गुप्ता शाहगंज,शिवकुमारी जी, लवकुश केशरी झूंसी, डॉ राकेश केसरवानी बाबूगंज,रोहित केशरी हनुमानगंज, गिरिजेश केसरवानी हनुमानगंज, रामबाबू केशरी फूलपुर, जयप्रकाश केशरी फूलपुर, कुवंर केशरी फूलपुर, अनुज केशरी झूंसी, दीपक केशरी झूंसी, रामबाबू केशरी (पूर्व सांसद) झूंसी, रामजी केशरी फूलपुर, राजेन्द्र केशरी सहसों, दिनेश केशरी धूमनगंज, नीरज पटेल अंदावा टी एन दीक्षित, हरीश केसरवानी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

श्री रामलखन चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था भविष्य में भी इसी प्रकार जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी।

दिन मे रेकी कर रात्रि को चोरी की घटनाओ को दे रहे थ अंजाम

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। दिन मे रेकी कर रात्रि को चोरी की घटनाओ को अंजाम देने वाले एक शातिर चोरो के गिरोह के 5 सदस्यों को जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे से दो अवैध तमंचा व घटना मे प्रयुक्त होने वाली बाईक 29 हजार की नगदी चोरी के जेवरात व बर्तन बरामद किये।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जहाँगीराबाद पुलिस ने मुनीमाबाद शराब ठेके के निकट से

जहाँगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अटवा निवासी मनोज कुमार पुत्र स्व0 विद्याप्रसाद जनपद सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम लखनापुर निवासी नीलू पुत्र विक्रम घुंघेटर थाना क्षेत्र के ग्राम अटहरा निवासी दयाराम पुत्र स्व0 पाटन व उमेश पुत्र प्यारेलाल महमूदाबाद जनपद सीतापुर के ग्राम जाफरपुर निवासी रविन्द्र पुत्र बदलू को गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे व निशांदेही से चोरी का एक पीतल का बटुआ, 05 जोड़ी चांदी की पायल 12 जोडी चांदी की बिछिया 05 अदद चांदी अंगूठी 02 अदद सोने की अंगूठी पीली धातु 01 अदद सोने का मांग टीका पीली 1 अदद सोने की नथुनी 1 अदद सोने के टप्स 2 अदद पीतल का लोटा 1अदद परात पीतल 1 अदद चैन चांदी की 01 अदद मोबाइल एंड्राएड पोको कम्पनी सहित. 29 हजार की नगदी चोरी मे प्रयुक्त पल्सर व 02 अदद अवैध तमंचा .12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद किया।

थानाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शुक्ला ने बताया कि चोरो का एक शातिर गिरोह है जो दिन मे बाईक से रेकी करते है और रात्रि

में चिन्हित घर में चोरी की घटना का अंजाम देते है चोरो ने 29 अक्टूबर की रात्रि मे जहाँगीराबाद क्षेत्र के ग्राम फैजुल्लागंज में एक घर का ताला तोड़कर चोरी करने एव 1 नवम्बर था जहाँगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बल्लापुरवा मजरे अजगना मे घर की दीवार तोड़कर चोरी करने एव 21 नवम्बर को जहाँगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम इल्मासगंज से घर में सेंध लगाकर चोरी करने तथा थाना फतेहपुर व मो0पुर खाला क्षेत्रान्तर्गत भी चोरी करने की बात को कुबूल किया। पुलिस की गिरफ्त मे आये चोरो के विरुद्ध थाना जहागीराबाद सहित सीतापुर मे अपराधिक मुकदमे दर्ज है।